जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 16 संख्याः 240 प्रभात चूरू, शुक्रवार 27 दिसम्बर, 2024 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

सी.डब्ल्यु.सी. की बेलगावी बैठक में कुछ ठोस नहीं हुआ: बैठक केवल प्रतीकात्मक ही रही!

तीन घंटे की बैठक में कांग्रेस ने संविधान, अंबेडकर का अपमान, जातिगत जनगणना के बारे में अपनी चिर-परिचित सोच को दोहराया

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सी.डब्ल्यु.सी.) की बहु-प्रचारित मीटिंग, जो कर्नाटक के बेलगावी में हुई, वास्तविक से कहीं ज्यादा, प्रतीकात्मक थी।

मीटिंग में उस ऐतिहासिक दिन को बड़ी श्रद्धा के साथ याद किया, जब, भारत लौटने के बाद, महात्मा गांधी आज से 100 वर्ष पहले 26 दिसम्बर को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाये गये थे। कांग्रेस ने नरेन्द्र मोदी की राजनीति के विरुद्ध अपने रुख तथा सोच, चाहे वह संविधान के बारे में हो, भीमराव अम्बेडकर के बारे में हो या विदेश नीति के बारे में हो, को दोहराया। मीटिंग में इस बिन्दु विचार हुआ कि जातीय जनगणना कराये जाने, तथा दलितों, पिछड़ों तथा अन्य वर्गों के लिये आरक्षण बढ़ाने के लिये संघर्ष को किस तरह आगे बढ़ाया जायेगा। लेकिन संगठन के बारे में न के बराबर ही चर्चा हुई। खड़गे ने यह जरुर कहा कि पूरे संगठन का ढाँचा बदला जायेगा तथा सुधार किया जायेगा, खाली पद भरे जायेंगे तथा सभी वर्गों को समुचित स्थान दिया जायेगा। उन्होंने, कुल मिलाकर, संगठन को पटरी पर लाने की जरुरत बताई।

- कांग्रेसाध्यक्ष ने यह जरूर कहा था बैठक के पहले कि संगठन में आमूल परिवर्तन पुनर्गठन होगा। रिक्त पद भरे जायेंगे तथा सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा।
- उदयपुर में भी संगठन के बारे में ऐसे कई निर्णय लिये गये थे, कोई सा भी निर्णय क्रियान्वित नहीं हुआ है।
- तीन घंटे की बैठक में इस बात पर कुछ भी मंथन नहीं हुआ कि आखिर पार्टी की हालत इतनी गड़बड़ क्यों है तथा पार्टी अब चुनाव जीतने की कला कैसे भूल गई है।
- तथा राहुल गांधी उस सही आदमी को क्यों नहीं ढूंढ पाये, जो संगठन के छोटे-मोटे सभी निर्णय ले सके तथा पार्टी का चार्ज संभाल ले।
- एक वरिष्ठ पार्टी नेता ने बैठक के बाद टिप्पणी की कि केवल मोदी की आलोचना करने से कुछ होने वाला नहीं है। फोकस पार्टी पर होना चाहिए तथा चुनाव जीतने पर होना चाहिए।

उदयपुर में भी, संगठन के सम्बंध में बहुत से निर्णय लिये गये थे, लेकिन अब तक उनमें से किसी पर भी अमल नहीं हुआ है। तीन घंटे की इस प्रतीकात्मक मीटिंग में इन बिन्दुओं पर कोई गहन चर्चा नहीं हुई कि कांग्रेस की असली बीमारी क्या है, अब यह चुनाव जीतने वाली पार्टी क्यों नहीं रही है तथा राहुल संगठन का सही माइक्रोमैनेजमेंट तलाशने में असमर्थ क्यों रहे हैं।

सोनिया गांधी सी.डब्ल्यू.सी. में उपस्थित नहीं हुई थीं, लेकिन उन्होंने सदस्यों के लिये एक संदेश भेजा था।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि नरेन्द्र मोदी की आलोचना करते रहने से कांग्रेस को चुनाव जीतने में कोई मदद नहीं मिलनी है।

पार्टी, तथा चुनाव जीतने पर फोकस जरुरी है।

सी.डब्ल्यू.सी. के प्रस्ताव में राहुल गांधी द्वारा प्रायः दोहराये जाने वाले उनके प्रिय बिन्दु ही थे, जिन्हें वे हर अवसर पर दोहराते रहते हैं।

राहुल गांधी ने अपने भाषण में

(शेष पृष्ठ 3 पर)

डॉ.मनमोहन सिंह का निधन

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। गुरुवार शाम अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें आठ बजे दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के इमरजेंसी वॉर्ड में भर्ती कराया गया, रात 9:51 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।

- शाम को अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें एम्स में भर्ती कराया था। दो घंटे बाद उनका देहान्त हो गया।

मनमोहन सिंह लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्यों का सामना कर रहे थे। इससे पहले भी उन्हें कई बार स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है।

इस खबर के बाद कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्युसी) की मीटिंग रद्द कर दी गई है। साथ ही 27 दिसंबर को होने वाले सभी प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिए

(शेष पृष्ठ 3 पर)

आर.एस.एस. के मुख पत्र ने मोहन भागवत की टिप्पणी की आलोचना की

भागवत ने कहा था कि राम मंदिर बनने के बाद कई नेता यह मानने लगे हैं कि कई जगहों पर ऐसे मंदिर-मस्ज़िद विवाद उठाकर वे हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, जो गलत है

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर। एक के बाद एक मंदिर-मस्जिद विवादों के उठाए जाने पर मोहन भागवत की आलोचनापूर्ण टिप्पणियों को लेकर हिन्दू संतों द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त किये जाने के बाद, आर.एस.एस. के मुख पत्र, ऑर्गनाइज़र ने भी प्रतिकूल रुख अपनाते हुये कहा है कि "विवादित स्थलों तथा इमारतों का वास्तविक इतिहास जानना सभ्यता संबंधी न्याय के लिए महत्वपूर्ण है।"

पुणे के एक समारोह में भागवत ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद, कुछ लोग इस विचार से प्रेरित प्रतीत हो रहे हैं कि वे इस प्रकार के विवाद खड़े करके हिन्दुओं के नेताओं के रूप में उभर सकते हैं।

हिन्दू संतों के एक संगठन, अखिल भारतीय संत समिति ने भागवत की आलोचना की तथा कहा कि सबसे अच्छी बात यह होगी कि इस प्रकार के मामलों का निर्णय आर.एस.एस. नहीं करे तथा यह काम धार्मिक नेताओं के लिये छोड़ दिया जाये। समिति के महासचिव, स्वामी जितेन्द्रानन्द सरस्वती ने कहा था, "जब धर्म का विषय उठता है, तो उसका निर्णय करना धार्मिक गुरुओं का काम है और वे जो भी निर्णय लेंगे, वह संघ और वी.एच.पी. (विश्व हिन्दू परिषद) को स्वीकार होगा।"

"ऑर्गनाइज़र" के ताजा अंक की कवर स्टोरी में यही बात कही गई है, हालाँकि, ऑर्गनाइज़र ने भागवत के नाम का उल्लेख नहीं किया है। संपादकीय में यह तर्क दिया गया है कि संभल की शाही जामा मस्जिद के स्थान पर मंदिर था। ऑर्गनाइज़र में प्रकाशित लेख कहता है, "जिन धार्मिक स्थलों पर अतीत में हमला हुआ या ध्वस्त कर दिया गया, उनसे संबंधित सच को समझना महत्वपूर्ण है।"

- मुख पत्र ऑब्ज़र्वर की राय इसके विपरीत है, उसने कहा कि किसी भी हिंदू/मुस्लिम स्थल का इतिहास जानना जरुरी है, जिससे सांस्कृतिक न्याय मिल सके। इसी से दोनों समुदायों के बीच स्थाई शांति व सद्भाव बना रहेगा।
- साथ ही यह भी कहा है कि "अण्डरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रुथ" आवश्यक है। यह जानना जरुरी है कि विदेशी आक्रमण के बाद धार्मिक स्थल किस तरह से नष्ट हुए।

ये सारी घटनाएं एवं चर्चा ऐसे समय पर हो रही हैं, जब अदालतों में ऐसी अनेक याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, जिनमें संभल की शाही जामा मस्जिद से लेकर अजमेर के दरगाह तक, देश के विभिन्न भागों में स्थित मुस्लिम मस्जिदों तथा मक़बरों के सर्वे की माँग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने नये मंदिर-मस्जिद मुकदमों को फिलहाल रोक देने के आदेश जारी कर दिये हैं।

लेकिन ऑर्गनाइज़र ने दलील दी है कि इतिहास की सच्ची समझ सभ्यता-संबंधी न्याय (सिविलाइज़ेशनल जस्टिस) प्राप्त करने तथा सभी समुदायों के बीच शान्ति और सामंजस्य को बढ़ाने के लिये अत्यावश्यक है।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

युवा दलित नेता हो सकता है भाजपा का अगला अध्यक्ष?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का सामना करने के लिये पार्टी अध्यक्ष पद के लिये किसी दलित युवा नेता का चयन कर सकती है।

- चर्चा है कि अंबेडकर के मुद्दे पर भाजपा को दलित विरोधी करार देने के कांग्रेस के प्रचार को मात देने के लिए भाजपा यह कदम उठाने पर विचार कर रही है।

बुधवार को भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के निवास पर एन.डी.ए. नेताओं की मीटिंग हुई तथा शाह द्वारा बाबासाहेब अंबेडकर के अपमान के कांग्रेस के आरोपों की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस जनता का ध्यान खींचने के लिए यह सब कर रही है।

15 लाख रूपए सालाना आय पर आयकर में कटौती हो सकती है?

रॉयटर्स ने बताया कि भारत सरकार आगामी बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के उपायों पर विचार कर रही है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर। कहा जा रहा है कि सरकार सालाना 15 लाख रूपए कमाने वालों के लिए आयकर में कटौती करने जा रही है। इससे लाखों शहरी करदाताओं को लाभ हो सकता है। रॉयटर्स ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा कि वर्ष 2025-26 के केन्द्रीय बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने और खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार कई उपाय घोषित कर सकती है।

इस प्रस्ताव से करदाता को 2020 की कर प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिसमें मकान किराए जैसी छूट समाप्त कर दी गई है, पर इसमें आयकर की दरें कम हैं। इस प्रणाली के तहत 3 से 15 लाख रूपए के बीच की आय पर 5 से 20 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है तथा 15 लाख रूपए से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है। विशेष रूप से नए टैक्स सिस्टम में 3 लाख रूपए की आय पर 0 प्रतिशत, 3 से 7 लाख रूपए की आय पर 5 प्रतिशत,

- भारत में अभी इन्कम टैक्स की दो व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, पुरानी में मकान किराया और बीमा पर टैक्स राहत दी जाती है, पर नई व्यवस्था में 3 से 15 लाख रूपए सालाना आय पर 5 से 20 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है।
- नई प्रणाली में तीन से सात लाख रूपए सालाना आय पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख रूपए पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रूपए पर 15 प्रतिशत और 12 से 15 लाख रूपए सालाना आय पर 20 प्रतिशत तथा 15 लाख से अधिक आय पर 30 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है।
- सरकार 15 लाख रूपए तक की आय पर इनकम टैक्स घटा कर मध्यम वर्ग को नई टैक्स प्रणाली की ओर आकर्षित करना चाहती है। अभी यह तय नहीं है कि कितनी कटौती होगी।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

गत वर्ष में तीन सर्वोच्च स्तर के सेना अधिकारी बर्खास्त किये गये हैं चीन में

इन बर्खास्तगियों का कारण औपचारिक रूप से भ्रष्टाचार बताया जाता है, पर, वास्तविक कारण है, राष्ट्रपति ज़ी को किसी भी तरह से चुनौती देने वाले सैन्य संगठन में कभी पनप ही नहीं पायें

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर। चीन अपने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के ढांचे में व्यापक बदलाव कर रहा है। एक प्रमुख न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग के अनुसार, मिलिटरी हायरार्की (सैन्य पदानुक्रम) के उच्च स्तर पर लोगों को बर्खास्त किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ने इसे मुख्य रुप से भ्रष्टाचार और अधिकारियों द्वारा धन कमाने के खिलाफ की गई कार्यवाही कहा है।

तथापि, जिस तरह से मुख्य अधिकारियों को निकाला जा रहा है, उसमें राजनीतिक एंगल नज़र आता है।

- लगातार, सेना के कमाण्ड स्ट्रक्चर में परिवर्तन करके, नेतृत्व की दृष्टि से राष्टपति ज़ी, किसी समान्तर, "पावर सैन्टर" (सत्ता के केन्द्र) को उगने ही नहीं देते।
- पर, "कमाण्ड स्ट्रक्चर" में लगातार ही अधरझूल की स्थिति बने रहने के दुष्प्रभाव भी हैं। छोटे से देश वियतनाम के समक्ष युद्ध में चीन को घुटने टेकने पड़े थे।
- पर, यह भी सच है कि विश्व की सबसे विशाल चीन की सेना, जिसमें दो करोड़ सैनिक हैं, के लिये साज, सामान, इमारतों का निर्माण लगातार द्रुत गति से हरदम चलता है। दोनों मदों में भारी धन राशि खर्च होती है। अतः भ्रष्टाचार का भी पूरा "स्कोप" बना रहता है।

कम्युनिस्ट पार्टी जनरल सैक्रेटरी और चीन के राष्ट्रपति, शी जिनपिंग लगातार अपनी सुप्रीम पावर प्रमाणित करना और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि देश में कोई समानान्तर "पावर सैंटर" (सत्ता का केन्द्र) नहीं हो।

सैंट्रल मिलिटरी कमिशन, जो चीन के सैन्य मामलों में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है, में अब, अध्यक्ष शी जिनपिंग के अलावा केवल दो ही सदस्य हैं। रक्षा मंत्री तथा कमिशन के अन्य सदस्यों सहित, छः अधिकारियों को पिछले कुछ सालों में हटा दिया गया है।

लगातार हो रहे बदलाव तथा उच्च

(शेष पृष्ठ 3 पर)

राजस्थान सरकार

अपील

प्रिय नागरिकों,

हमारे राज्य में सड़क दुर्घटनाओं और इनसे होने वाली मौतें हम सभी के लिए एक गहरी चिंता का विषय हैं। ये दुःखद घटनाएं हमारे समाज के कई घरों में अंधकार ला देती हैं—किसी मां से उसका बेटा छीन लेती हैं, किसी बच्चे को अनाथ बना देती हैं। इस पीड़ा को समझते हुए, मैं आपसे संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ अपील कर रहा हूँ।

सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और पीड़ितों की जीवन रक्षा के लिए हमने 6E रणनीति (एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर, इवैल्यूएशन और एंगेजमेंट) को अपनाते हुए समन्वित प्रयास करने का निर्णय लिया है लेकिन यह प्रयास तभी सफल हो सकता है, जब आप सभी का सहयोग और समर्थन हमारे साथ हो। आइए, हम मिलकर इस गंभीर चुनौती का सामना करें और अपने परिवार एवं समाज को सुरक्षित रखें।

आपकी सुरक्षा के लिए यह कदम उठाएं:

1. सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें: हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें। यह एक छोटा कदम है, लेकिन आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
2. ट्रैफिक नियमों की जानकारी लें: सड़क सुरक्षा की शिक्षा हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। अपने बच्चों को भी इन नियमों के प्रति जागरूक बनाएं।
3. रात्रि वाहन चालन में सावधानी बरतें: हाई बीम लाइट का उपयोग न करें और शराब पीकर वाहन चलाने से बचें। अपने प्रियजनों के बारे में सोचें और सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित अपने घर लौट सकें।
4. दुर्घटना की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दें: तुरंत आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और घायलों की सहायता करें। हर जीवन मूल्यवान है और आपकी त्वरित मदद किसी की जान बचा सकती है।

आप सभी से आग्रह है कि अपने समुदाय और स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लें।

आइए, हम सभी यह संकल्प लें कि अपने राज्य को सड़क दुर्घटनाओं से मुक्त बनाएंगे। आपका सुरक्षित जीवन हमारे लिए सर्वोपरि है।

धन्यवाद।

भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री, राजस्थान

राजस्थान संवाद

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित